Drishti IAS

करेंट अफेयर्स झारखंड

जनवरी 2023 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखंड **3**

- झारखंड को 3 नये एयरपोर्ट की मिलेगी सौगात 3
- झारखंड में बच्चे को गोद लेने के लिये सिविल सर्जन से लेनी होगी मंज़ूरी 4
- कोडरमा व चतरा में खुलेगा रिजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर 4
- जमशेदपुर 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' में शामिल 4
- DVC लगायेगा 2200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट 5
- झारखंड के किसानों के लिये बनेगा 'चेंबर ऑफ फॉर्मर्स' 6
- श्री सम्मेद शिखरजी को ईको टूरिज़्म ज़ोन एवं पर्यटन से हटाया गया 6
- जमशेदपुर पुलिस ने क्यूआर कोड आधारित बीट सिस्टम अपनाया 7
- राष्ट्रपति ने कोडरमा ज़िला प्रशासन को दिया डिजिटल इंडिया अवार्ड 8
- 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर शिक्षा देने की तैयारी पूर्ण 8
- टुसू महोत्सव 9
- भारत से चयनित 6 विद्यालयों में झारखंड से एकमात्र DPS बोकारो को मिला 7 स्टार रेटिंग अवार्ड 9
- रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 10
- राँची मौसम केंद्र भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित 10
- झारखंड का पहला 'बर्तन बैंक' खुला 11
- ऐन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) 2022 11
- अरविंद वर्णवाल ने केदारकांठा पर्वत की 12050 फीट ऊँची चोटी पर फहराया तिरंगा 12
- जल संरक्षण योजना 13
- झारखंड में मोटे अनाज की खेती को मिलेगा बढ़ावा 13
- मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों की आश्रितों को किया सम्मानित 14
- डीएवी बोकारो की आना सिन्हा व ईशान कुमार झा इंस्पायर अवार्ड के लिये चयनित 14
- 'झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिये विधेयक, 2022' को राज्यपाल ने वापस लौटाया 15
- धनबाद के धनेश्वर ने जीता स्ट्रांग मैन ओपन पावर लिफ्टिंग पुरस्कार 16

नोट :

झारखंड

झारखंड को 3 नये एयरपोर्ट की मिलेगी सौगात

चर्चा में क्यों ?

1 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार नये साल में झारखंड को 3 नये एयरपोर्ट के तोहफों के रूप में राँची और देवघर के अलावा अब पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के अलावा बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी। इस तरह से राज्य में कुल पाँच एयरपोर्ट हो जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि राज्य के बोकारो वासियों के लिये एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो गया है। जून तक यहाँ से विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। 15 जनवरी, 2023 के आसपास एयरपोर्ट परिचालन संबंधित उच्चस्तरीय बैठक होगी, जिसमें शेष बचे कार्य को पूरा किया जाएगा।
- 'उड़ान' योजना के तहत बोकारो एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट कोलकाता के लिये शुरू होगी। इसके लिये स्पाइस एयरवेज ने एयरपोर्ट प्रबंधन से वार्ता की है। इसके बाद पटना-बोकारो फ्लाइट शुरू करने की योजना है। यात्रियों की डिमांड पर यहाँ से बेंगलुरु और दिल्ली के लिये फ्लाइट शुरू करने की भी योजना है।
- राज्य के पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के लिये संपर्क मार्ग को लेकर ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले दिनों जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय नागरिक उडन्यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर इस एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है। इसी के तहत इसके निर्माण को लेकर तैयारी शुरू हो गई है।
- झारखंड में तीसरा नया एयरपोर्ट दुमका में बनेगा। इस एयरपोर्ट के होने से यहाँ के लोगों को राँची और कोलकाता जाने में सहूलियत होगी। इसको लेकर सांसद सुनील सोरेन ने नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर दुमका में हवाई सेवा शुरू करने का आग्रह किया था।
- विदित है कि पूर्व में पीएम मोदी ने दुमका एयरपोर्ट राज्यवासियों को देने की बात कही थी। दुमका झारखंड की उपराजधानी भी है।
- राज्य के देवघर एयरपोर्ट में कई नयी सुविधाएँ शुरू होने वाली है। देवघर एयरपोर्ट में डीवीओआर (वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेज डाप्लर रडार) लगाने का काम पूरा हो चुका है। जनवरी तक डीवीओआर चालू होने की संभावना है। इससे देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी।
- इसके अलावा देवघर एयरपोर्ट से राँची, पटना, बेंगलुरु और मुंबई के लिये हवाई सेवा चालू करने की योजना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कई एयरलाइंस कंपनियों से नयी उड़ान चालू करने के लिये वार्ता हो रही है।
- नये साल में देवघर एयरपोर्ट कार्गो विमान सेवा चालू करने की भी योजना है, जिससे संथाल परगना, गिरिडीह समेत बिहार के भागलपुर, बांका और जमुई इलाके को औद्योगिक गति मिलेगी।
- देवघर एयरपोर्ट यूनिट ने डीजीसीए को देवघर एयरपोर्ट से कार्गो सेवा चालू करने का प्रस्ताव भी भेज दिया है। एयरपोर्ट में काम करनेवाले कर्मियों व अधिकारियों के लिये एयरपोर्ट कैंपस में ही एरोसिटी डेवलप करने की योजना है, जिसे वर्ष 2023 में धरातल पर उतारा जा सकता है। एरोसिटी को कॉमर्शियल रूप भी दिया जा सकता है।

नोट :

झारखंड में बच्चे को गोद लेने के लिये सिविल सर्जन से लेनी होगी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

1 जनवरी, 2023 को झारखंड बालगृह एवं दत्तक ग्रहण संस्था करुणा एनएमओ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य दत्तक ग्रहण नियमावली-2022 के नियम-37 के अनुसार, ज़िला अस्पताल प्रबंधन की ओर से प्रमाण-पत्र निर्गत करना अनिवार्य किया गया है, जिसमे अब बच्चे को गोद लेने के लिये सामाजिक संस्था और लोगों को सिविल सर्जन से अनुमति लेनी होगी।

प्रमुख बिंदु

- नियम के अनुसार, अगर किसी परिचित, नर्सिंग होम, अस्पताल या किसी एनजीओ से बच्चे की सूचना मिलती है, तो उसके आधार पर आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। इसके तहत सिविल सर्जन द्वारा बनाया गया मेडिकल बोर्ड पहले बच्चे को देख-समझकर उसका भौतिक सत्यापन (फिजिकल टेस्ट) करेगा कि बच्चा सामान्य कैटेगरी का है या फिर विशेष।
- गौरतलब है कि राज्य की बालगृह एवं दत्तक ग्रहण संस्था करुणा एनएमओ ने सिविल सर्जन कार्यालय को पत्र लिखकर दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रमाणपत्र निर्गत करने का आग्रह किया है। ऐसे में कोई भी परिवार अगर किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, तो उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने 11 अक्तूबर, 2022 को इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया था।
- यह संस्था मुख्य रूप से अनाथ, छोड़ दिये गए और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद दिलाने के लिये काम करती है।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में देश में लगभग तीन करोड़ 10 लाख अनाथ बच्चे हैं, लेकिन जटिल कानूनी प्रक्रिया के कारण पिछले पाँच सालों में सिर्फ 16,353 बच्चों को ही गोद लिया जा सका है।

कोडरमा व चतरा में खुलेगा रिजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर

चर्चा में क्यों ?

2 जनवरी, 2023 को झारखंड के कोडरमा के डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि राज्य के दो ज़िलों कोडरमा व चतरा में परिवहन विभाग द्वारा क्षेत्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, जिसके क्रियान्वयन को लेकर डीपीआर तैयार करने की स्वीकृति दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- कोडरमा डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि क्षेत्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिये कोडरमा में जयनगर व चंदवारा के करौंजिया में दो जगहों पर ज़मीन चिह्नित की गई है। इन दोनों में से बेहतर जगह पर करीब पाँच एकड़ ज़मीन पर केंद्र का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है, जिससे लोगों को आने वाले समय में सहूलियत प्राप्त होगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में झारखंड के सिर्फ धनबाद ज़िले में हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सरकारी तौर पर संचालित है।
- हैवी व्हीकल का लाइसेंस के लिये आवेदन करने वालों का धनबाद में ही ट्रायल लिया जाता है। इसके बाद लाइसेंस जारी किया जाता है। ऐसे में लंबे समय से अन्य ज़िलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इस मांग को देखते हुए श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने वैपीक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोहराबादी, राँची के द्वारा तैयार पीपीआर के तहत योजना के क्रियान्वयन को लेकर अनुमोदन किया है।
- उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए कई व्यवस्थाएँ रहेंगी।

जमशेदपुर 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' में शामिल

चर्चा में क्यों ?

3 जनवरी, 2023 को झारखंड के जमशेदपुर अक्षेस विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पर्यावरण से जुड़े 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' में जमशेदपुर को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्य से राँची और धनबाद भी इसमें शामिल हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जमशेदपुर अक्षेस विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने जमशेदपुर में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिये लगभग 50 करोड़ रुपए का अग्रिम आवंटन किया है।
- इसके लिये जमशेदपुर अक्षेस, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद संयुक्त कार्य योजना बनाएंगे। इसमें जमशेदपुर अक्षेस नोडल एजेंसी होगी।
- संजय कुमार ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण पार्षद व निकाय मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। जुगसलाई और मानगो चौक पर प्रदूषण मापक यंत्र स्थापित किया जा चुका है। इस योजना में बीआईटी मेसरा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है।
- उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बीआईटी मेसरा पता लगाएगा कि किस सोर्स से प्रदूषण हो रहा है। सड़कों पर उड़ने वाले धूल कण को नियंत्रित किया जाएगा। जहाँ सबसे ज्यादा धूलकण होते हैं, वहाँ पेवर्स ब्लॉक लगाया जा रहा है।
- टूटी सड़कों को तत्काल ठीक कराया जायेगा तथा सड़कों के चौड़ीकरण की भी योजना है। इसके अंतर्गत पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाई जाएगी तथा करीब तीन हज़ार नये पेड़ लगाने की योजना पर काम तेजी से चल रहा है।

DVC लगायेगा 2200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट

चर्चा में क्यों ?

4 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) अपने कमांड एरिया में 2200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगा। ये कमांड एरिया के अलग-अलग इलाकों में लगाए जाएंगे। इसका डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- डीवीसी के सूत्रों ने बताया कि यहाँ दो हज़ार मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिये दो हज़ार मेगावाट बिजली की योजना का डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है।
- मैथन, तिलैया और पंचेत डैम में 600-600 मेगावाट की क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा, कोनार डैम में 200 मेगावाट क्षमता का प्लांट लगेगा। वहीं, 200 मेगावाट का सोलर प्लांट फील्ड में लगाया जाएगा। इसमें रूफ टॉप भी शामिल है।
- 200 मेगावाट के लिये कोडरमा, मैथन व डीवीसी के कमांड एरिया में अध्ययन कराया जा रहा है। जल्द ही डीपीआर भी तैयार कर लिया जाएगा। पहले चरण में 10 मेगावाट के प्लांट के लिये कोडरमा में स्थल चयन कर लिया गया है।
- जानकारी के अनुसार सोलर प्लांट के साथ-साथ हाइडल प्लांट पर भी डीवीसी काम कर रहा है। गिरिडीह में सरना धर्मावलंबियों के पवित्र स्थल लुगुबुरु में हाइडल प्लांट लगाने को लेकर अध्ययन किया गया है। यहाँ 1500 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज हाइडल प्लांट की योजना पर काम चल रहा है। इसका डीपीआर तैयार होते ही इसे राज्य व केंद्र सरकार की मंजूरी के लिये भेजा जाएगा। उसके बाद अगले बजट में इस योजना को शामिल किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि तिलैया डैम डीवीसी द्वारा निर्मित यह पहला बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन है जो की बराकर नदी पर बनाया गया है। यह बांध 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊँचा है।
- मैथन डैम बराकर नदी के तट पर स्थित है। यह झारखंड के धनबाद ज़िले के कोयला शहर से लगभग 48 किमी. दूर स्थित है। अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला यह बांध पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में अद्वितीय है।
- पंचेत बांध झारखंड में धनबाद ज़िले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर बनाया गया है। इसका उद्घाटन वर्ष 1959 में किया गया। पंचेत बांध 4 मल्टी-प्रयोजन बांधों में से चौथा बांध है, जो दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में आता है।

नोट :

झारखंड के किसानों के लिये बनेगा 'चेंबर ऑफ फॉर्मर्स'

चर्चा में क्यों ?

5 जनवरी, 2023 को झारखंड की उद्यान निदेशक निशा उरांव ने सभी उपायुक्त को पत्र लिखकर बताया कि राज्य के धनबाद ज़िले के किसानों के लिये 'चेंबर ऑफ फॉर्मर्स' बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उद्यान निदेशक निशा उरांव ने बताया कि धनबाद में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' के तहत इस वर्ष मोटे अनाज के उत्पाद एवं मार्केटिंग पर फोकस होगा, जिसके लिये चेंबर ऑफ फॉर्मर्स का गठन किया जाएगा।
- राज्य सरकार ने चेंबर ऑफ फॉर्मर्स के संबंध में संकल्प भी जारी कर दिया है, जिसके लिये 210 लाख रुपए अनुदान के रूप में स्वीकृत भी किया गया है तथा सभी डीसी को ज़िला उद्यान पदाधिकारी के जरिये इसका गठन कराने को कहा गया है।
- चेंबर ऑफ फॉर्मर्स के गठन का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं व्यवसायियों के बीच मार्केट लिंकेज की संभावना को बढ़ावा देना है। इसके लिये ज़िला स्तरीय सहयोग समिति बनाने की भी तैयारी चल रही है।
- चेंबर ऑफ फॉर्मर्स के गठन की प्रक्रिया के लिये जल्द ही इसकी पूरी कमेटी गठित हो जाएगी। इसमें कुछ विभागीय अधिकारियों के अलावा प्रगतिशील किसानों को शामिल किया जाएगा।

श्री सम्मेद शिखरजी को ईको टूरिज़्म ज़ोन एवं पर्यटन से हटाया गया

चर्चा में क्यों ?

5 जनवरी, 2023 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने झारखंड के गिरिडीह ज़िले में स्थित श्री सम्मेद शिखरजी पर्वत क्षेत्र से जुड़े पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचना की धारा 3 के प्रावधानों और अन्य सभी पर्यटन और ईको-पर्यटन गतिविधियों को लागू करने पर तत्काल रोक रोक लगा दी है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेश यादव को इस संबंध में पत्र लिखा था। सीएम ने पत्र के माध्यम से कहा था कि पारसनाथ सम्मेद शिखर पौराणिक काल से ही जैन समुदाय का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल रहा है। मान्यता के अनुसार जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पिछले कुछ दिनों में पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य में होने वाली कुछ गतिविधियों के बारे में जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों से कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जिससे जैन धर्म के अनुयायियों की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- इन शिकायतों में झारखंड सरकार द्वारा पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना के प्रावधानों का दोषपूर्ण कार्यान्वयन का उल्लेख है और कहा गया है कि राज्य सरकार की इस तरह की लापरवाही से उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची है।
- इस संबंध में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पूरे मुद्दे और संभावित समाधान पर चर्चा करने के लिये जैन समुदाय के विभिन्न प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके साथ एक बैठक की थी। प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आए और उन्होंने सम्मेद शिखरजी की वर्तमान स्थिति और स्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिये समुदाय की मांगों के बारे में बात की।
- प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि पारसनाथ डब्ल्यूएल अभयारण्य की स्थापना तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा 1984 में वन्यजीव संरक्षण कानून, 1972 के प्रावधानों के तहत की गई थी, जबकि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजैड) को पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार ने झारखंड की सरकार के साथ परामर्श से 2019 में अधिसूचित किया था।
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को प्रतिबंधित, नियंत्रित और बढ़ावा देकर संरक्षित क्षेत्रों के लिये एक प्रकार का 'शॉक एब्जॉर्बर' के रूप में कार्य किया जाता है।

नोट :

- ईएसजैड अधिसूचना का उद्देश्य अनियंत्रित पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं है, और निश्चित रूप से अभयारण्य की सीमा के भीतर हर प्रकार की विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना नहीं है। ईएसजैड की घोषणा वास्तव में अभयारण्य के आसपास और इसलिये, इसकी सीमा के बाहर गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिये है।
- पारसनाथ डब्ल्यूएल अभयारण्य की प्रबंध योजना में पर्याप्त प्रावधान हैं जो जैन समुदाय की भावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं, भारत सरकार जैन समुदाय की भावनाओं को देखते हुए समग्र रूप से निगरानी समिति को किसी भी समस्या का समाधान करने के लिये दिशा निर्देश जारी कर सकती है।
- केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि मंत्रालय स्थापित तथ्य को स्वीकार करता है कि सम्मेद शिखरजी पर्वत क्षेत्र न केवल जैन समुदाय के लिये बल्कि पूरे देश के लिये एक पवित्र जैन धार्मिक स्थान है और मंत्रालय इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिये प्रतिबद्ध है।
- बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड की सरकार को पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य की प्रबंध योजना के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया जाए, जो विशेष रूप से वनस्पतियों या जीवों को नुकसान पहुँचाने, पालतू जानवरों के साथ आने, तेज संगीत बजाने या लाउडस्पीकरों का उपयोग करने, स्थलों या धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों जैसे पवित्र स्मारक, झीलों, चट्टानों, गुफाओं और मंदिरों को गंदा करने; और शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री; पारसनाथ पहाड़ी पर अनधिकृत शिविर और ट्रेकिंग आदि को प्रतिबंधित करता है।
- झारखंड सरकार को निर्देशित किया गया है इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन करे। राज्य सरकार को पारसनाथ पहाड़ी पर शराब और माँसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
- इसके अलावा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत उपरोक्त पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी के लिये, केंद्र सरकार ने इस अधिसूचना की धारा 5 के तहत एक निगरानी समिति का गठन किया है।
- राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि जैन समुदाय से दो सदस्य और स्थानीय आदिवासी समुदाय से एक सदस्य को इस निगरानी समिति में स्थायी आमंत्रित के रूप में रखा जाए, जिससे महत्त्वपूर्ण हितधारकों द्वारा उचित भागीदारी और निरीक्षण किया जा सके।

जमशेदपुर पुलिस ने क्यूआर कोड आधारित बीट सिस्टम अपनाया

चर्चा में क्यों ?

6 जनवरी, 2023 को पूर्वी सिंहभूमि ज़िले के एसएसपी प्रभात कुमार ने जमशेदपुर के साकची स्थित कंपोजिट कंट्रोल रूम (सीसीआर) में क्यूआर कोड स्कैनिंग सिस्टम के जरिये स्मार्ट पुलिसिंग का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- जमशेदपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में फैले 1500 से अधिक बीट पॉइंट्स ने क्यूआर कोड-आधारित ई-बीट सिस्टम को अपनाया है। नई प्रणाली के तहत, जमशेदपुर पुलिस की गश्ती टीमों के पास ज़िले भर में स्कैन-थ्रू क्यूआर कोड होंगे।
- संबंधित थानों के प्रभारी अधिकारियों को क्यूआर कोड की स्कैनिंग के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी के साथ डेटा बनाए रखना होगा ताकि गश्त करने वाले दल अपने कर्तव्य से बच न सकें।
- पिछली पारंपरिक लॉगबुक प्रणाली के तहत, बीट पुलिस को अपनी धड़कनों के साथ स्थापित स्वाइपिंग मशीनों के माध्यम से मैन्युअल रूप से अपने मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना पड़ता था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में हेरफेर की गुंजाइश थी क्योंकि उचित निगरानी नहीं थी।
- नई प्रणाली के साथ, बीट पुलिस को अपने मोबाइल फोन से अपने मार्गों पर रखे क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। ऐप आधारित क्यूआर कोड चेहरे की पहचान का उपयोग करता है और पुलिस अधिकारियों को बेहतर और त्वरित प्रतिक्रिया के लिये फोटो डाउनलोड करने और टिप्पणियाँ लिखने की अनुमति देता है। कंट्रोल रूम से भी सिस्टम की रियल टाइम आधार पर मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

नोट :

- जैसे ही बीट पुलिसकर्मी कोड को स्कैन करेगा, प्रभारी अधिकारी को न सिर्फ कन्फर्मेशन मिलेगा, बल्कि जीपीएस के जरिये उसकी गतिविधि को भी ट्रैक किया जा सकेगा। ऐप में दर्ज की गई टिप्पणियों को भविष्य की पुलिसिंग और योजना के लिये संगृहीत और विश्लेषण किया जा सकता है।
- नई प्रणाली के शुभारंभ के दौरान एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि शुरुआत में साकची में 27 क्यूआर और बिस्टुपुर में 30 क्यूआर कोड लगाए गए हैं।
- ये क्यूआर कोड प्रमुख आभूषण दुकानों, बैंकों और होटलों में स्थापित किये गए हैं, जहाँ गश्त करने वाली पार्टियों को नियमित रूप से नजर रखनी होती है। ज़िले भर में जल्द ही ऐसे क्यूआर कोड की संख्या बढ़ाकर 1,500 की जाएगी, ताकि निर्दोष पुलिस पेट्रोलिंग से व्यवसायियों, बैंकों, स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षित किया जा सके।

राष्ट्रपति ने कोडरमा ज़िला प्रशासन को दिया डिजिटल इंडिया अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

7 जनवरी, 2023 को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रास रूट लेवल पर आम लोगों खासकर युवाओं को कंप्यूटर की जानकारी उपलब्ध करवाने को लेकर किये गए बेहतर कार्य के लिये झारखंड के कोडरमा ज़िला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कोडरमा के डीसी आदित्य रंजन ने ग्रहण किया।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि कोडरमा झारखंड का एकमात्र ज़िला है, जिसे यह सम्मान मिला है।
- जानकारी के अनुसार डीसी आदित्य रंजन की पहल पर पाँच सितंबर, 2021 को समाहरणालय परिसर में ज़िले का पहला डीईजीएस कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हुई थी। इस सेंटर को मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद मरकच्चो प्रखंड को छोड़कर कोडरमा, झुमरीतिलैया, सतगावाँ, डोमचांच, चंदवारा व जयनगर में इस केंद्र की शुरुआत की गई। दो अन्य केंद्र की शुरुआत चार जनवरी को की गई थी।
- कोडरमा के डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि वर्तमान में चल रहे आठ डीईजीएस कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की संख्या बढ़ाकर जल्द 11 की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष करीब 20 हज़ार लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने की दिशा में इन सेंटरों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने इस कॉन्सेप्ट के तहत हुए कार्य को देखते हुए डिजिटल इंडिया अवार्ड देने के लिये कोडरमा का चयन किया था। कोडरमा डीसी आदित्य रंजन ने आठ दिसंबर को दिल्ली में बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की योजना को ज्यूरी के समक्ष रखा था।
- उल्लेखनीय है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड को लेकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने 2022 में आवेदन आमंत्रित किये थे। इसके लिये हज़ारों की संख्या में नॉमिनेशन हुए थे।
- सात अलग-अलग कैटेगरी में दिये जाने वाले अवार्ड को लेकर हुए फर्स्ट राउंड के शार्ट लिस्ट में 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट को जगह मिली थी। इसके बाद नौ सदस्यों की ज्यूरी के समक्ष सभी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था।

80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर शिक्षा देने की तैयारी पूर्ण

चर्चा में क्यों ?

10 जनवरी, 2023 को झारखंड जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य में शुरू होने वाले 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएससी की तर्ज पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इसके लिये झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने तैयारी पूर्ण कर ली है।

प्रमुख बिंदु

- 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में से 48 विद्यालयों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। शेष 32 विद्यालयों का निर्माण अंतिम चरण में है, जो मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा। अप्रैल से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र से सभी 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन सीबीएसई की संबद्धता के साथ की जाएगी।

नोट :

- राज्य के 24 उत्कृष्ट विद्यालयों का सीबीएसई से संबद्धता हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये सीबीएसई द्वारा संबद्धता प्रदान कर दी गई है। शेष 56 उत्कृष्ट विद्यालयों को भी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से संबद्धता के लिये आवश्यक सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी करते हुए संबद्धता प्राप्त हो जाएगी।
- जनवरी 2023 में सीबीएसई द्वारा सभी 80 उत्कृष्ट विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को सीबीएसई के अनुरूप विद्यालय संचालन हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
- राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय एवं 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों हेतु हर्ष जोहार कार्यक्रम बच्चों को हैप्पीनेस करिकुलम के आधार पर शिक्षित करने के लिये तैयार किया गया है। इसके लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है तथा हर्ष हैप्पीनेस करिकुलम तैयार किया गया है। विद्यालयों में यह 27 जनवरी से प्रारंभ होगा।

टुसू महोत्सव

चर्चा में क्यों ?

11 जनवरी, 2023 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्विद्यालय (डीएसपीएमयू) राँची में टुसू महोत्सव (Tusu Festival) का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर परंपरा के अनुसार कुंवारी छात्राओं द्वारा टुसू की विधिवत स्थापना कर पूजा-अर्चना की गई, इसके बाद टुसू माता का विसर्जन किया किया गया
- कुलपति डॉ. डॉ तपन कुमार शांडिल्य ने कहा कि टुसू पर्व झारखंड के प्रमुख पर्व में से एक है, जो झारखंडी सभ्यता के अनुसार साल का अंतिम पर्व है।
- इसी दिन से सूर्य कर्क रेखा की ओर लौटने के क्रम में मकर रेखा पर होता है, जिसे झारखंडी संस्कृति में कृषि नव वर्ष अखाइन जतरा के रूप में मनाया जाता है।
- इसी दिन धान बुनकर तथा हल चलाकर सांकेतिक कृषि कार्य का प्रारंभ किया जाता है। यह टुसू पर्व झारखंड के कुड़मी और आदिवासियों का सबसे महत्त्वपूर्ण पर्व है।

भारत से चयनित 6 विद्यालयों में झारखंड से एकमात्र DPS बोकारो को मिला 7 स्टार रेटिंग अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

11 जनवरी, 2023 को आयोजित एक विशेष असेंबली के दौरान दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के प्राचार्य डॉ. एएस गंगवार ने बताया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो को 7 स्टार रेटिंग स्कूल अवॉर्ड 2022 मिला है।

प्रमुख बिंदु

- यह अवार्ड डीपीएस बोकारो को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्व-निर्वहन एवं विभिन्न अनूठे पहलों के लिये दिया गया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल को ग्रीन स्कूल इनीशिएटिव की विशेष कैटेगरी में सेवन स्टार रेटिंग और ए- ट्रिपल प्लस की ग्रेडिंग मिली।
- उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट (सीईडी) फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से कौशल शिक्षा एवं सतत् विकास विषय पर आयोजित आठवें सम्मेलन के दौरान प्राचार्य डॉ. एएस गंगवार को सम्मेलन की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला द्वारा यह पुरस्कार दिया गया।
- गौरतलब है कि देशभर से कुल 1975 विद्यालयों के आवेदनों में से केवल छह विद्यालयों को सेवेन स्टार रेटिंग मिली। इनमें झारखंड से अकेले डीपीएस बोकारो शामिल रहा, वहीं, 69 स्कूलों को फाइव स्टार रेटिंग मिली।
- प्राचार्य डीपीएस बोकारो ने अपने गो ग्रीन इनीशिएटिव के तहत प्रकृति से बच्चों को जोड़े रखने तथा ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई अनूठी व कारगर पहल की है।

नोट :

- यहाँ रद्दी कागज को रीसाइकिल कर पुन: उपयोग के लायक बनाने के लिये पेपर रीसाइक्लिंग यूनिट, सौर-ऊर्जा से संचालित सोलर पैनल सिस्टम, औषधीय पौधों की चरक वाटिका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, महापुरुषों के नाम पर पौधशाला (ग्रीन ब्रिगेड) आदि की स्थापना की गई है।
- इसके अलावा केंचुआ खाद से कृषि कार्य के लिये वर्मी कल्चर, जैविक कृषि वानिकी तथा मिट्टी बचाने के लिये सेव सॉइल, बच्चों को प्रकृति-पोषण से जोड़े रखने के लिये फुलवारी, विभिन्न अवसरों पर पौधारोपण एवं स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिये ग्रीन आई कार्ड, विभिन्न अवसरों पर अतिथियों के लिये फल-सब्जियों के बीज वाले विशेष ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ-साथ पौधे भेंटकर अतिथियों का ग्रीन वेलकम करने की परंपरा भी विगत कई वर्षों से निभाई जा रही है।

रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

11 जनवरी, 2023 को झारखंड के रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई प्रेस कांफ्रेंस में टेक्नो इंडिया झारखंड परियोजना के उप निदेशक विष्णु चटोपाध्याय ने बताया कि राज्य के इस कॉलेज में उन्नत अनुकूलन तकनीकों और अनुप्रयोगों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-2023 का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- टेक्नो इंडिया झारखंड परियोजना के उप निदेशक विष्णु चटोपाध्याय ने बताया कि यह कार्यक्रम 21 और 22 जनवरी को कॉलेज में ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में होगा, यह उन्नत अनुकूलन तकनीकों और अनुप्रयोगों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा।
- इसका आयोजन रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा सुल्तान मौले स्लीमेन यूनिवर्सिटी, मलेशिया के सहयोग से किया जा रहा है। यह सम्मेलन ओप्टीमाइजेशन एंड कंम्प्युटिंग विषय पर आधारित होगा।
- इस सम्मेलन में दो देशों के प्रख्यात वक्ता एवं भारत के विभिन्न प्रसिद्ध कॉलेजों के वक्ता भी शामिल होंगे। इनके अलावा सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो, सरला बिड़ला विश्वविद्यालय से गोपाल पाठक, टीडीयू वियतनाम से डॉ. बुइ थान हंग, यूएनएम यूएसए से डॉ. फ्लोरेंटिन स्मारंदचे, आईआईटी जोधपुर से डॉ. तन्मय कुंडू, एमआरआईआईएस से डॉ. अनिता खोसला, भारत केआईआईटी विश्वविद्यालय से डॉ. सुशांत त्रिपाठी और एएमयू से डॉ. इरफान अली शामिल होंगे।
- रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज की प्राचार्या डॉ. श्रावणी रॉय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये किया जा रहा है, जिससे युवा शोधकर्त्ताओं को भी प्रेरणा मिलेगी और किसी भी काम से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह विभिन्न देशों के कॉलेजों के बीच लिंक बनाने में सहायक साबित होगा।

राँची मौसम केंद्र भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित

चर्चा में क्यों ?

15 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली के मौसम भवन के 'वृष्टि सभागार' में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 148वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में राँची मौसम केंद्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस समारोह में रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने देश के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार ग्रहण किया।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुरकंडा जी, मुरारी देवी, जोत और बनिहाल टॉप के डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा कई प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया।

नोट :

झारखंड का पहला 'बर्तन बैंक' खुला

चर्चा में क्यों ?

16 जनवरी, 2023 को झारखंड के गुमला ज़िले के डीसी सुशांत गौरव और गुमला नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण उरांव ने शहर में झारखंड के पहले बर्तन बैंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए गुमला नगर परिषद ने यह पहल की है।

प्रमुख बिंदु

- गुमला ज़िले के डीसी सुशांत गौरव ने बर्तन बैंक को सर्कुलर इकोनॉमी का बेहतर उदाहरण देते हुए नगर परिषद की इस पहल को अभिनव तथा अनुकरणीय बताया है।
- नगर परिषद अध्यक्ष दीपनारायण उरांव ने बताया कि ज़्यादातर लोग शादी-ब्याह, सालगिरह और बर्थडे पार्टी जैसे आयोजनों में भोजन-पानी सर्व करने के लिये थर्मोकोल प्लेट और प्लास्टिक गिलास जैसे सस्ते साधन उपयोग करते हैं। फिर उस आयोजन के बाद यही थर्माकोल और प्लास्टिक बर्तन प्रदूषित कूड़ा बनकर शहर को गंदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
- प्लास्टिक और थर्माकोल के बर्तनों को मात देने और पर्यावरण संरक्षण के लिये नगर परिषद प्रशासन ने शहर के जरूरतमंद नागरिकों को स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने के लिये यह बर्तन बैंक खोला है।
- नगर परिषद उपाध्यक्ष कलीम अख्तर ने बताया कि नगर परिषद ने अपने खर्चे पर बड़ी संख्या में स्टील की थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी आदि खरीदे हैं। लोगों की मांग पर उन्हें कुछ शर्तों पर ये स्टील के बर्तन सेट महज एक रुपया दर पर या अत्यंत गरीब होने पर नि:शुल्क भी उपयोग करने के लिये उपलब्ध होगा। लेकिन, लोगों की भी ज़िम्मेदारी रहेगी कि वे थर्माकोल और प्लास्टिक गिलासों का उपयोग न करें।
- कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इस बर्तन बैंक के संचालन का ज़िम्मा महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया है, ताकि बर्तन के प्रतीकात्मक किराये से आने वाली राशि से संबंधित महिला समूह की आय में कुछ न कुछ वृद्धि हो सके।
- सदर एसडीओ रवि जैन ने कहा कि शहर को साफ-सुथरा रखना और पर्यावरण की रक्षा करना सबका दायित्व है और इस दायित्व को निभाने में कुछ न कुछ भूमिका यह बर्तन बैंक भी जरूर निभाएगा।
- डीसी सुशांत गौरव ने बताया कि खिलौना बैंक और बर्तन बैंक की तर्ज पर गुमला में पुस्तक बैंक भी बनाया जा सकता है।

ऐन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) 2022

चर्चा में क्यों ?

18 जनवरी 2023 को जारी ऐन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) 2022 के अनुसार झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ रहा है।

प्रमुख बिंदु

- ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कक्षा 8 तक में नामांकित कुल बच्चों में से 3 फीसदी सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। असर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में निजी विद्यालयों में मात्र 14.6 फीसदी बच्चे ही पढ़ते हैं।
- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या 78 फीसदी थी। इस दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या में 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
- यह सर्वे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बीच किया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में कक्षा 1 से 8 तक के 9 फीसदी बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, इस वर्ष इनकी संख्या बढ़ कर 45.3 फीसदी हो गई है। इस दौरान ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में आठ फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इस दौरान ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

नोट :

- राज्य में कक्षा बढ़ने के साथ ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती है। सर्वे राज्य के 24 ज़िलों के 720 गाँवों में किया गया। इनमें तीन वर्ष से 16 वर्ष तक के 28196 बच्चों को शामिल किया गया।
- इस रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 3 के बच्चे पढ़ाई में पहले की तुलना में कमज़ोर हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में कक्षा 3 के 7 फीसदी बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते थे, पर वर्ष 2022 में यह संख्या घटकर 14.3 फीसदी हो गई।
- इस रिपोर्ट के अनुसार कक्षा तीन के 4 फीसदी बच्चे अक्षर नहीं पहचान पाते हैं।
- कक्षा पाँच के 2 फीसदी बच्चे ही कक्षा एक के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कक्षा पाँच में पढ़ने वाले 30.7 फीसदी बच्चे 11 से 99 तक के अंक को पहचान पाते हैं, जबकि 78 फीसदी बच्चे घटाव तो 76 फीसदी बच्चे भाग नहीं बना पाते।
- कक्षा छह के 3 फीसदी बच्चे घटाव तो 30.7 फीसदी बच्चे भाग बना पाते हैं। कक्षा सात के 25.4 फीसदी बच्चे घटाव तो 41.1 फीसदी बच्चे भाग बना पाते हैं। कक्षा आठ के 25.8 फीसदी बच्चे घटाव तो 45.3 फीसदी बच्चे भाग बना पाते हैं।
- इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अंग्रेजी की पढ़ाई में बच्चे कमज़ोर हैं। कक्षा एक के 1 फीसदी बच्चे बड़े अक्षर नहीं पहचान पाते हैं। कक्षा के दो के 30 फीसदी, कक्षा तीन के 18.2 फीसदी, कक्षा चार के 12.2 फीसदी व कक्षा पाँच के 7.8 फीसदी बच्चे अंग्रेजी के बड़े अक्षर नहीं पहचान पाते हैं।
- कक्षा तीन के 8 फीसदी बच्चे अंग्रेजी के वाक्य पढ़ सकते हैं, जबकि कक्षा आठ में 33.5 फीसदी बच्चे वाक्य पढ़ पाते हैं। ऐसे में कक्षा आठ के लगभग 77 फीसदी बच्चे अंग्रेजी के सरल वाक्य नहीं पढ़ पाते हैं।
- इस रिपोर्ट की मुख्य बातें- 1 फीसदी स्कूलों में पेयजल की सुविधा है लेकिन 11.3 फीसदी स्कूलों में पेयजल नहीं, राज्य के 21.1 फीसदी स्कूलों में शौचालय उपयोग के लायक नहीं, 27.1 फीसदी विद्यालयों में पुस्तकालय के पुस्तकों का उपयोग नहीं हो रहा, 92.1 फीसदी स्कूलों में बिजली कनेक्शन पर सर्वेक्षण के दिन 73.1 फीसदी स्कूलों में बिजली नहीं थी, 91.5 फीसदी स्कूलों में बच्चों के उपयोग के लिये कंप्यूटर नहीं, राज्य में 89.6 फीसदी ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ कक्षा एक व दो के बच्चे एक साथ बैठते हैं।
- गौरतलब है कि एक गैर-सरकारी संगठन 'प्रथम'इस रिपोर्ट को जारी करता है।

अरविंद वर्णवाल ने केदारकांठा पर्वत की 12050 फीट ऊँची चोटी पर फहराया तिरंगा

चर्चा में क्यों ?

18 जनवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के जामताड़ा के अरविंद वर्णवाल ने हिमालय पर्वत श्रृंखला के केदारकांठा पर्वत की 12050 फीट की ऊँचाई पर गणतंत्र दिवस के पूर्व तिरंगा फहराकर देश को गौरवान्वित किया है।

प्रमुख बिंदु

- अरविंद वर्णवाल ने बताया कि पूरे भारत वर्ष से आठ राज्यों के 30 लोग गणतंत्र दिवस के पूर्व हिमालय पर्वत श्रृंखला पर तिरंगा फहराने की यात्रा में शामिल थे, जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के ट्रेकर शामिल थे।
- उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के ट्रेकर त्रिलोक राय के नेतृत्व में उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित हिमालयन श्रृंखला के केदारकांठा पर्वत शिखर की 12050 फीट की ऊँचाई पर तिरंगा फहराने के लिये संकरी गाँव से यात्रा शुरू की थी। संकरी गाँव से 12 किमी. पर केदारकांठा पर्वत था।
- इस पर्वत को फतह करने के दौरान दो बेस कैंप बनाए गए थे। पहला बेस कैंप पर्वत के तलहटी में, तो दूसरा बेस कैंप 10,000 फीट की ऊँचाई पर था।
- विदित है कि अरविंद वर्णवाल पहले भी अमरनाथ और केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं।
- अरविंद वर्णवाल ने बताया कि 15 जनवरी को देहरादून से यात्रा शुरू की थी। वहाँ से मसूरी, नावगाँव, पुरोला, मूरी, नेटवाद कोटगाँव (संकरी) तक 220 किमी. का सफर करीब दस घंटे में पहुँचा।
- 16 जनवरी को दूसरे दिन, कोटगाँव (संकरी) से केदारकांठा पर्वत के 9100 फीट पर स्थित पहले बेस कैंप पहुँचे तथा 17 जनवरी को तीसरे दिन 11250 फीट पर स्थित दूसरे बेस कैंप शेफर्ड कैंप करीब पाँच घंटे की ट्रेकिंग कर पहुँचे। उसके बाद करीब चार घंटे की चढ़ाई के बाद 18 जनवरी को सुबह 7 बजे केदारकांठा की सबसे ऊँची चोटी पर पहुँचे और तिरंगा फहराया।

नोट :

जल संरक्षण योजना

चर्चा में क्यों ?

21 जनवरी, 2023 को झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के सूखे का सामना कर रहे किसानों को लाभ पहुँचाने के लिये 32 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 'जल संरक्षण योजना'की शुरूआत की।

प्रमुख बिंदु

- एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 'जल संरक्षण योजना'के तहत राज्य के 24 ज़िलों के सभी ब्लॉकों में 2,133 तालाबों का नवीनीकरण और 2,795 परकोलेशन टैंकों का निर्माण किया जाएगा।
- इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 71 तालाबों और 184 परकोलेशन टैंकों के नवीनीकरण कार्य की भी आधारशिला रखी।
- विदित है कि एक परकोलेशन टैंक भूजल भंडारण को रिचार्ज करने के लिये एक कृत्रिम रूप से निर्मित सतह जल निकाय है।
- कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार को सूखा प्रभावित किसानों से 33 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से 8.5 लाख को अब तक वित्तीय सहायता दी गई है।
- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास यह है कि सूखा प्रभावित 30 लाख किसानों को जल्द ही राहत के तौर पर 1,200 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएँ।
- उल्लेखनीय है कि झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साल 29 अक्टूबर को राज्य के 260 प्रखंडों में से 226 को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था और बारिश की कमी से प्रभावित प्रत्येक किसान परिवार को 3,500 रुपए की नकद राहत देने का फैसला किया है।

झारखंड में मोटे अनाज की खेती को मिलेगा बढ़ावा

चर्चा में क्यों ?

26 जनवरी, 2023 को झारखंड कृषि विभाग ने भारत सरकार के आदेश के आलोक में मोटे अनाज (मिलेट्स) को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके लिये अब विभाग की इकाई समिति ने 10 करोड़ रुपए की योजना बनाई है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना में आने वाले सालों में झारखंड के विभिन्न ज़िलों में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है। राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने की पूरी संभावनाएँ हैं। यहाँ पहले कई प्रकार के मोटे अनाज उत्पन्न होते थे।
- उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग पिछले दो साल से अपने बड़े कार्यक्रम में मोटे अनाज के उत्पाद ही अतिथियों को परोसता है। कृषि विभाग की कार्यशाला में मडुआ की रोटी, मडुआ का पीठा, छिलका रोटी आदि परोसा जाता है।
- कृषि विभाग मोटे अनाज की उपयोगिता और संभावना पर राज्य से लेकर प्रखंड स्तर पर सेमिनार का आयोजन करेगा।
- ज्ञातव्य है कि भारत सरकार वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने भी योजना तैयार की है। इसमें मोटे अनाज पर काम करने वाले विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी।
- झारखंड में रागी उत्पादन की अच्छी संभावना है। एपिडा की रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड में 15 हज़ार टन के करीब रागी का उत्पादन होता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में यहाँ 18 हज़ार टन के करीब उत्पादन हुआ था। ज्वार का भी उत्पादन करीब एक हज़ार टन हो रहा है। यह तब हो रहा है, जब सरकार की प्राथमिकता सूची में यह नहीं था।
- इकाई समिति के निदेशक अजय कुमार ने बताया कि राज्य में वर्षों पहले से मोटे अनाज की खेती होती थी। यहाँ के जनजातीय समुदाय मोटे अनाज की भरपूर की खेती करते थे। बाज़ार नहीं होने के कारण इसको बढ़ावा नहीं मिल सका।
- उन्होंने बताया कि अब मोटे अनाज को बाज़ार की दिक्कत नहीं है। यह बाज़ार में काफी महंगा भी बिक रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि यह पूरी तरह आर्गेनिक फसल है। इसमें कीटनाशक की ज़रूरत नहीं होती है और यह कम पानी में तैयार हो जाता है।
- विदित है कि झारखंड में समय-समय पर सूखा पड़ जाता है। इसको देखते हुए झारखंड के लिये मोटे अनाज की खेती काफी कारगर साबित होगी।

नोट :

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों की आश्रितों को किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

26 जनवरी, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य की उप-राजधानी दुमका में आयोजित समारोह में तीन स्वतंत्रता सेनानियों की आश्रित पत्नियों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता सेनानी स्व. धनेश्वर मंडल की पत्नी चंद्रावती देवी (ग्राम- बंदरी, प्रखंड- सरैयाहाट, ज़िला- दुमका), स्व. पतरू राय की पत्नी परवतिया देवी (ग्राम- परसदाहा, प्रखंड- सरैयाहाट, ज़िला- दुमका) एवं स्व. दशरथ राय की पत्नी सरोतिया देवी (ग्राम- डेलीपाथर, प्रखंड- रामगढ़, ज़िला- दुमका) को सम्मानित किया।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली एसएसबी 35 बटालियन और झाँकियों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झाँकी को प्रथम पुरस्कार से नवाजा। इसके अलावा बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को भी सम्मानित किया गया।
- पुरस्कृत होने वाली परेड टुकड़ी:
  - प्रथम पुरस्कार - एसएसबी 35 बटालियन
  - द्वितीय पुरस्कार - आईआरबी- 1 जामताड़ा
  - तृतीय पुरस्कार - एनसीसी, दुमका
- इन विभागों की झाँकियों को मिला पुरस्कार:
  - प्रथम पुरस्कार - ज़िला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, दुमका
  - द्वितीय पुस्कार - ज़िला उद्योग विभाग
  - तृतीय पुरस्कार - ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं वन विभाग
- बेहतर कार्य के लिये सम्मानित होने वाले पदाधिकारी और कर्मी - शिकारीपाड़ा के प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार चौधरी, सविता कुमारी (एएनएम), लखपति देवी (सेविका), राजीव रंजन (चालक), विकास कुमार अग्रवाल (पेंटिंग)।

डीएवी बोकारो की आना सिन्हा व ईशान कुमार झा इंस्पायर अवार्ड के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से इंस्पायर अवार्ड के लिये डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-06 की कक्षा 9 की आना सिन्हा व कक्षा 6 के ईशान कुमार झा का चयन हुआ है। दोनों प्रतिभागी विज्ञान व तकनीक की सहायता से समाज, राज्य व राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- आना सिन्हा ने पोर्टेबल एंड फोल्डिंग टेबल विषय पर अपनी खोज पूर्ण की है। इनके द्वारा बनाया गया पोर्टेबल एंड फोल्डिंग टेबल विद्यार्थियों के पठन-पाठन में उपयोगी है। इस टेबल के उपयोग से विद्यार्थी सही पोस्चर में बैठकर काम करते हैं। इसको आसानी से खोल सकते या मोड़ सकते हैं। इसमें ज़रूरी कागज़ात व सामान भी रख सकते हैं। यह लकड़ी का बना हुआ टेबल है।
- वहीं ईशान कुमार झा ने हैंड्स बैग विथ सेंसर बनाया है। इसके माध्यम से बैग की चोरी होने पर सेंसर के माध्यम से तुरंत पता चल जाता है। यदि अन्य जगह पर भी इसका प्रयोग होता है तो सेंसर के माध्यम से खोलते वक्त या रखते वक्त इसकी जानकारी तुरंत मिल जाती है। आएदिन हो रही बैग की चोरी की घटना को देखते हुए ईशान ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिये काम किया है।
- उल्लेखनीय है कि साइंस और प्रौद्योगिकी के प्रति स्टूडेंट्स में इंट्रेस्ट बढ़ाने के लिये केंद्र सरकार ने इंस्पायर अवार्ड्स मानक योजना शुरू की है। यह योजना देशभर के सभी मान्यताप्राप्त सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 6वीं से 10वीं के स्टूडेंट्स के लिये है।
- केंद्र सरकार की इंस्पायर अवार्ड्स मानक योजना के लिये चयनित स्टूडेंट्स को 10-10 हज़ार रुपए प्रदान किये जाते हैं। यह राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।

नोट :

- इंस्पायर अवाड्र्स मानक योजना के तहत ज़िला लेवल पर 10 हज़ार और राज्य लेवल पर 1 हज़ार स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, जबकि पूरे देश से 1 लाख स्टूडेंट्स का चयन किया जाता है।
- इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को मॉडल तैयार करना होता है। नेशनल लेवल पर चुने गए मॉडल को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले प्रवर्तन उत्सव में प्रदर्शित किया जाता है। चयनित स्टूडेंट्स को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत साइंस नेशनल लेवल पर जिस स्टूडेंट का चयन किया जाता है, उसे नगद पुरस्कार की राशि दी जाती है। वहीं, चुनिंदा स्टूडेंट्स को विदेश यात्रा करने का अवसर मिलता है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रतिस्पर्धा के ज़रिये छात्रों में साइंस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

'झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिये विधेयक, 2022' को राज्यपाल ने वापस लौटाया

चर्चा में क्यों ?

29 जनवरी, 2023 को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से पारित 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित 'झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिये विधेयक, 2022' को राज्यपाल रमेश बैस ने समीक्षा के लिये वापस लौटा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल ने विधेयक को लौटाते हुए राज्य सरकार से कहा है कि इस विधेयक की वैधानिकता की गंभीरतापूर्वक समीक्षा करें कि यह संविधान के अनुरूप एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों व निर्देशों के अनुरूप हो।
- उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही झारखंड मुक्ति मोर्चा, कॉन्ग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (झामुमो-कॉन्ग्रेस-राजद) की महागठबंधन सरकार ने 'झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिये विधेयक, 2022' को 11 नवंबर, 2022 को ध्वनिमत से पारित करके अनुमोदन के लिये राज्यपाल के पास भेजा था।
- इस विधेयक में कहा गया था कि झारखंड में स्थानीय व्यक्ति वे लोग कहलाएंगे, जो भारत के नागरिक होंगे और झारखंड की क्षेत्रीय एवं भौगोलिक सीमा में निवास करते हैं। उसके पूर्वज के नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण/खतियान में दर्ज़ हैं।
- इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी के हकदार होंगे।
- विधेयक की समीक्षा में पाया गया कि संविधान की धारा 16 में सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त हैं। संविधान की धारा 16(3) के अनुसार सिर्फ संसद को विशेष प्रावधान के तहत धारा 35(A) के अंतर्गत नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्त लगाने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है।
- गौरतलब है कि ए.वी.एस. नरसिम्हा राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश एवं अन्य (AIR 1970 SC 422) में भी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्त लगाने का अधिकार केवल भारतीय संसद में ही निहित है। इस प्रकार यह विधेयक संविधान के प्रावधान तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है।
- झारखंड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है, जो पाँचवीं अनुसूची में आता है। उक्त क्षेत्रों में शत-प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को नियोजन में आरक्षण देने के विषय पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया जा चुका है। इस आदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्तियों की शर्त लगाने की राज्यपाल में निहित शक्तियों को भी संविधान की धारा 16 के विपरीत घोषित किया था।
- सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य द्वारा दिये गए शत-प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। विदित है कि विधि विभाग ने स्पष्ट किया था कि प्रश्नगत विधेयक के प्रावधान संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत हैं। साथ ही कहा गया है कि ऐसे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट एवं झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप नहीं हैं।

नोट :

- विधि विभाग ने यह भी कहा कि ऐसा प्रावधान स्पष्टत: भारतीय संविधान के भाग-III के अनुच्छेद 14, 15, 16 (2) में प्रदत्त मूल अधिकार से असंगत व प्रतिकूल प्रभाव रखने वाला प्रतीत होता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से भी प्रभावित होगा तथा अनावश्यक वाद-विवादों को जन्म देगा।

धनबाद के धनेश्वर ने जीता स्ट्रांग मैन ओपन पावर लिफ्टिंग पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

29 जनवरी, 2023 को बिहार के धनबाद में जीसीईटी सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित चौथे ओपन कोयलांचल क्लासिक महिला एवं पुरुष पावर लिफ्टिंग एवं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ, जिसमें धनबाद के धनेश्वर ने स्ट्रांग मैन ओपन पावर लिफ्टिंग पुरस्कार जीता।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि चौथे ओपन कोयलांचल क्लासिक महिला एवं पुरुष पावर लिफ्टिंग एवं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ 27 जनवरी को हुआ था।
- प्रतियोगिता में धनबाद के धनेश्वर कुमार राय को स्ट्रांग मैन ओपन पावरलिफ्टिंग, मो. रूस्तम आलम को सब जूनियर बेस्ट लिफ्टर (बेंच प्रेस), दीपक गोप को सब जूनियर बेस्ट लिफ्टर (डेड लिफ्ट), नितेश राना को जूनियर बेस्ट लिफ्टर (बेंच प्रेस), इस्तियाक अंसारी को सीनियर बेस्ट लिफ्टर (बेंच प्रेस), आदित्य कुमार को जूनियर बेस्ट लिफ्टर (डेड लिफ्ट), धनेश्वर राय को सीनियर बेस्ट लिफ्टर (डेड लिफ्ट) का पुरस्कार मिला।
- ओपन पावर लिफ्टिंग की महिला विजेताओं में शिखा, सोना रावल, सिन्नी कुमारी (52 किग्रा.), ज्योति कुमारी (57 किग्रा.), मनीषा लकड़ा (72 किग्रा.), नमिता नायक (63 किग्रा.) एवं गिरिडीह की खुशी लाल (84 किग्रा.) शामिल हैं।

The Vision

नोट :